

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894

No. 379] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 14th August 1972

No. 555(E).—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. S.O. 1482, dated the 31st March, 1971, the management of the Industrial Undertaking known as Messrs Gresham and Craven of India (Private) Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 31st day of March, 1971;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a scheduled industry namely, Railway Rolling Stock;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the industrial undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the 31st day of March, 1971, shall remain suspended.

2. This order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 2/5/72-P.S. Cell-HM(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1972

का० आ० 555(अ).—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1482, तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा प्रेसर्स प्रेशरिंग एण्ड क्रेन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध को औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के अधीन 31 मार्च, 1971 से आरम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए ले लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में अनुसूचित उद्योग अर्थात् रेल रोलिंग स्टॉक में उत्पादन की मात्रा को कम होने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि सभी संविदाओं के लागू होने, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्र, अन्य लिखित करार, समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखित जो प्रवृत्त हैं, जिनमें औद्योगिक उपक्रम पक्षकारी या जो उस पर 31 मार्च 1971 से तुरन्त पहले लागू होती है, निरन्तर रहेगी ।

2. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[सं० 2/5/72-पी० एम० सेल-एच एम (i)]

एम० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।